SarkariExam.com

28 जुलाई 2021

1. अफ्रीका के पूर्वी तट पर शुरू हुआ नौसैन्य अभ्यास 'कटलैस एक्सप्रेस-2021'

- 26 जुलाई से 6 अगस्त, 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट नौसैनिक समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2021 (Exercise Cutlass Express) में आईएनएस तलवार भाग ले रहा है। यह समुद्री अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है।
- कटलैस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में आईएनएस तलवार भाग ले रहा है। यह अभ्यास प्रवर्तन क्षमता में सुधार, संयुक्त समुद्री कानून और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

कटलैस एक्सप्रेस 2021 के प्रतिभागी

- 2021 संस्करण में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और विभिन्न अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO), यूरोपीय संघ नौसेना बल (EUNAVFOR) की भागीदारी शामिल है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना एक प्रशिक्षक की भूमिका में भाग ले रही है।
- आईएनएस तलवार केन्या में मोम्बासा का दौरा कर रहा है, जहां केन्या नौसेना के साथ इंटरेक्शन होगा। मोम्बासा में अपने प्रवास के दौरान, यह पोत भारतीय समुदाय और मेजबान के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा।
- आईएनएस तलवार की यह यात्रा सागर (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग की दिशा में भारत की नीति के अनुरूप है।

INS तलवार

- आईएनएस तलवार भारतीय नौसेना के तलवार-श्रेणी के युद्धपोतों या क्रिवक श्रेणी के

SarkariExam.com

स्टील्थ जहाज़ों का प्रमुख पोत/जहाज़है। 'मेक इन इंडिया' के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) द्वारा रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है। जहाज़ों के लिये इंजन की आपूर्ति यूक्रेन द्वारा की जा रही है।

- अक्टूबर, 2016 में भारत और रूस ने चार क्रिवाक या तलवार स्टील्थ फ्रिगेट के लिये एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर किये थे। पहले दो युद्धपोत रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में बनाए जाएंगे, जबकि अन्य दो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाएंगे। मौजूदा फ्रिगेट: नौसेना पहले से ही छह क्रिवाक III फ्रिगेट संचालित करती है। अप्रैल 2012 और जून 2013 के बीच बेड़े में शामिल हुए नए क्रिवाक युद्धपोत आईएनएस तेग, तरकश तथा त्रिकंद हैं।
- इनका उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन पनडुब्बियों एवं बड़े सतह जहाजों को खोजने और नष्ट करने जैसे विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करने हेतु किया जाता है।

2. असम के मुख्यमंत्री ने किया बाँस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास

- 26 जुलाई, 2021 को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने डिमा हासाओ के मांदेरडिसा गाँव (Manderdisa Village) में एक बाँस औद्योगिक पार्क (bamboo industrial park) की आधारशिला रखी है।
- परियोजना को डोनर मंत्रालय (DoNER ministry) से 50 करोड़ रुपये से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरूआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करेगी। डिमा हसाओ (Dima Hasao) में उत्पादित बाँस पहले ज्यादातर पेपर मिलों को निर्यात किया जाता था, हालांकि, पार्क के पूरा होने के साथ टाइल्स (tiles), अगरबत्ती (incense stick), छत (ceiling) आदि के उत्पादन के लिए बाँस का उपयोग करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे लोगों को अधिक आर्थिक लाभ होगा।

❑ राष्ट्रीय बाँस मिशन

- अक्टूबर 2006 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाँस मिशन (NBM) को राष्ट्रीय बाँस तकनीकी और

व्यापार विकास रिपोर्ट, 2003 के आधार पर लॉन्च किया था। राष्ट्रीय बाँस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में बाँस उद्योग के विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना, बाँस उद्योग को नई गति एवं दिशा प्रदान करना तथा बाँस उत्पादन में भारत की संभावनाओं को साकार करना है।

- बहु-अनुशासनात्मक और बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ यह मिशन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) या ग्राम विकास समितियों (VDCs) के माध्यम से योजनाबद्ध हस्तक्षेप, अनुसंधान और विकास, वन तथा गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण पर बल देता है। यह मिशन केंद्रीकृत और किसान/महिला नर्सरी की स्थापना करके गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है।

3. 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने मनाया अपना 83वाँ स्थापना दिवस

- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force -CRPF) ने 27 जुलाई 2021 को अपना 83वाँ स्थापना दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ की भूमिका अहम है।

❑ **केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (CRPF)**

- आंतरिक सुरक्षा के लिये यह भारत का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव्स पुलिस के रूप में 27 जुलाई, 1939 को CRPF अस्तित्व में आया।
- 28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम के द्वारा यह केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल बन गया। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA) के अधिकार के तहत सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली (New Delhi) में स्थित है। वर्तमान में आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह सीआरपीएफ महानिदेशक (CRPF Director General) है।

4. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का रखा प्रस्ताव

- 26 जुलाई, 2021 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि भारत सरकार देश में अनुसंधान

पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation- NRF) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' को एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो अनुसंधान व विकास, शिक्षा एवं उद्योग के बीच संबंधों में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

- 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' का कुल प्रस्तावित परिव्यय लगभग 50,000 करोड़ रुपए है और इसे आगामी पाँच वर्षों की अवधि में तैयार किया जाएगा। इस संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान तंत्र को विकसित करना तथा उसे सुविधाजनक बनाना है। इस संगठन की परिकल्पना 'नई शिक्षा नीति-2020' के तहत भी की गई है।
- वित्त आवंटन का अभाव प्रायः भारत में शोध और शोधकर्त्ताओं की कमी के सबसे बड़े कारणों में से एक है तथा इस फाउंडेशन का उद्देश्य इसी कमी को पूरा करना है। गौरतलब है कि देश में अनुसंधान के लिए आवंटित धन वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.84 प्रतिशत था, जो कि वर्ष 2014 में घटकर 0.69 प्रतिशत तक पहुँच गया, यह संयुक्त राज्य अमेरिका (2.8%), इज़राइल (4.3%) और दक्षिण कोरिया (4.2%) की तुलना में काफी कम है।

❑ **शिक्षा मंत्रालय**

- पूर्व में इसे मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था और यह मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। धर्मेंद्र प्रधान इस मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं।

5. ओडिशा में आपदा प्रबंधन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम किया जाएगा शामिल

- हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि यह कदम ओडिशा सरकार द्वारा 29 मई, 2021 को हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के निर्णय के बाद लिया गया है।
- इन पाठ्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य राज्य भर में छात्रों को आपदाओं के कारण उत्पन्न चुनौतियों जैसे कि बार-बार आने वाले चक्रवात एवं कोरोना वायरस महामारी आदि का सामना करने हेतु बेहतर तैयारी हेतु प्रशिक्षित करना है।
- गौरतलब है कि बीते दिनों चक्रवात यास ने राज्य में काफी नुकसान किया था और भारी बारिश, घरों को नुकसान पहुँचने, खेतों के नष्ट होने एवं विद्युत नेटवर्क के बाधित होने की घटनाएँ देखने को मिली थीं। 'ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट' 2020 के अनुसार, भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में पाँचवाँ सबसे संवेदनशील देश है।

- हाल के वर्षों में देश भर में भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और वनाग्नि की घटनाएँ काफी सामान्य हो गई हैं। संवेदनशील समुदायों, विशेष रूप से गरीबों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर जलवायु आपातकाल के गंभीर प्रभाव को देखते हुए इसे जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से लचीला बनाना काफी महत्त्वपूर्ण है।
- ऐसे में उच्च शिक्षा के स्तर पर आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम में शामिल करना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।

भारत में आपदा प्रबंधन हेतु संस्थागत संरचना

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने भारत में आपदा प्रबंधन हेतु कानूनी और संस्थागत संरचना का प्रावधान राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर किया है। भारत की संघीय राजनीति में आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित है।
- केंद्र सरकार योजनाएँ, नीतियां और दिशा-निर्देश तैयार करती है और तकनीकी, वित्तीय और संभरण सहायता देती है जबकि जिला प्रशासन केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ मिलकर अधिकांश कार्यों को सम्पन्न करता है।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिये एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है।
- केंद्रीय गृह सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना बनाने और राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के पास NDMA द्वारा सृजित व्यापक नीतियों और दिशा-निर्देशों के अधीन आपदा प्रबंधन के लिये मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण का अधिदेश है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)

- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) आपदा मोचन हेतु एक विशेषीकृत बल है और यह NDMA के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जून, 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) जारी की थी। देश में पहली बार इस तरह की राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है।

6. रूस ने स्पेस में भेजा नौका मॉड्यूल, 14 सालों के इंतजार के बाद हुई लॉन्चिंग

- हाल ही में रूस की स्पेस एजेंसी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी (Roscosmos) ने 'इंटरनेशनल

स्पेस स्टेशन' के लिए 'नौका' (Nauka) नाम से एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है, जो स्पेस स्टेशन पर देश की मुख्य अनुसंधान सुविधा के रूप में काम करेगा।

- ज्ञात हो कि अब तक रूस द्वारा 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' 'पीर' नाम से मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे मुख्यतः अनुसंधान और डॉकिंग पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 42 फीट लंबे और 20 टन वज़न वाले इस 'नौका' मॉड्यूल को मूलतः वर्ष 2007 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था। हालाँकि कई तकनीकी मुद्दों के कारण इसे अब तक लॉन्च नहीं किया जा सका था।
- 'नौका'- जिसका अर्थ रूसी भाषा में 'विज्ञान' है- रूस की अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है तथा यह मुख्य रूप से एक शोध सुविधा के रूप में काम करेगी। 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' पर 'नौका' मॉड्यूल को 'ज़्वेज़्दा मॉड्यूल' (Zvezda Module) से जोड़ा जाएगा, जो कि अंतरिक्ष स्टेशन पर 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' के रूप में कार्य करने के साथ ही 'रूसी ऑर्बिटल सेगमेंट' (ROS) के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

❑ **अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS)**

- यह एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है, जिसे 'लो-अर्थ ऑर्बिट' में मानव निर्मित सबसे बड़ा ढाँचा माना जाता है। इसका पहला हिस्सा वर्ष 1998 में 'लो-अर्थ ऑर्बिट' में लॉन्च किया गया था।
- यह लगभग 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और प्रतिदिन पृथ्वी की 15.5 परिक्रमाएँ पूरी करता है। 'अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन' कार्यक्रम पाँच प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त परियोजना है: नासा (अमेरिका), रॉसकॉसमॉस (रूस), जाक्सा (जापान), ESA (यूरोप) और CSA (कनाडा)।
- हालाँकि इसके स्वामित्व और उपयोग को अंतर-सरकारी संधियों और समझौतों के माध्यम से शासित किया जाता है। यह एक माइक्रोग्रैविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है जिसमें चालक दल के सदस्य जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और अन्य विषयों से संबंधित प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) के कारण ही 'लो-अर्थ ऑर्बिट' में निरंतर मानवीय उपस्थिति संभव हो पाई है। इसके वर्ष 2030 तक संचालित रहने की उम्मीद है।

7. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत वेब आधारित पोर्टल किया लॉन्च

- हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत आवेदन जमा करने तथा सहायता हासिल करने योग्य पात्र बच्चों की पहचान करने की सुविधा के लिए वेब-आधारित पोर्टल

pmcaresforchildren.in लॉन्च किया गया है।

- भारत, वर्तमान में कोविड-19 महामारी की दूसरी प्रचंड लहर से जूझ रहा है और इस महामारी के कारण कई बच्चों के माता-पिता की मृत्यु होने के मामलों में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही, इन बच्चों को गोद लेने की आड़ में बाल तस्करी की आशंका भी बढ़ गई है। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान 'बाल विवाह' संबंधी मामलों में भी वृद्धि हुई है।

❑ **पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन (PM CARES for Children)**

- यह योजना कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। कोविड 19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से किसी जीवित बचे अभिभावक या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर

❑ **इस योजना के प्रमुख बिंदु**

1. बच्चे के नाम पर सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट): 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का एक कोष गठित किया जाएगा।
2. स्कूली शिक्षा: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।
3. स्कूली शिक्षा: 11 -18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसेकि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा।
4. उच्च शिक्षा के लिए सहायता: मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी।
5. स्वास्थ्य बीमा: ऐसे सभी बच्चों को 'आयुष्मान भारत योजना' (PM-JAY) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।

8. भारत ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में जीते 5 गोल्ड सहित 13 पदक

- 25 जुलाई, 2021 को भारत ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में 13 पदक (5 स्वर्ण, 1 रजत, 7 कांस्य) के साथ समाप्त कर दिया है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 19 से 25 जुलाई, 2021 तक बुडापेस्ट, हंगरी में किया गया था।
- कैडेट विश्व चैंपियनशिप 16-17 वर्ष की आयु के बीच पहलवानों के लिए आयोजित एक वार्षिक आयोजन है। यह तीन श्रेणियों ग्रीको-रोमन, फ्रीस्टाइल और विमेंस रेसलिंग में आयोजित की जाती है। यह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा आयोजित की जाती है।
- चैंपियनशिप के आखिरी दिन प्रिया ने 73 किग्रा भारवर्ग के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की

पहलवान सेनिया पातापोविक को 5-0 से शिकस्त दी। प्रिया ने साल 2019 में पुणे में आयोजित हुए खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने उसी वर्ष दिल्ली में आयोजित 17वें स्कूल खेलों में भी स्वर्ण जीता था।

- साल 2020 में आयोजित हुए नेशनल स्कूल गेम्स और नेशनल कैडेट चैंपियनशिप में भी प्रिया ने स्वर्ण पदक जीते थे। तनु, कोमल, अमन गुलिया, सागर जगलान, चिराग और जयदीप भी फ्रीस्टाइल टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। जसकरण सिंह और भारत महिला कुश्ती टीम ने रजत जीता, जबकि अंकित गुलिया, वर्षा और साहिल को कांस्य से संतोष करना पड़ा। खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कैडेट चैंपियनशिप में भारत के युवा पहलवानों को दमदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

9. बाइडन ने इराक में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा

- 26 जुलाई, 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और इराक के प्रधानमंत्री मुस्तापा अल-कादिमी के बीच इराक में 18 साल बाद अमेरिकी सेना के लड़ाकू मिशन को खत्म करने पर समझौता हुआ है। दोनों नेताओं ने औपचारिक रूप से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते के अनुसार साल 2021 के अंत तक इराक में लड़ाकू मिशन खत्म हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने 18 साल पहले सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेकने के लिए इराक में सेना भेजी थी।
- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इराक में अमेरिकी लड़ाकू मिशन साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि इराक के साथ अमेरिकी संबंध अब एक नए चरण में प्रवेश करेंगे। इस्लामिक स्टेट के पुनरुत्थान के खतरे और बगदाद में ईरान के शक्तिशाली प्रभाव के बीच बाइडन ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन हमारे सुरक्षा सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
- अमेरिकी सेना इराकी बलों को आइएसआइएस (इस्लामिक स्टेट) के खिलाफ प्रशिक्षण और सहायता देना जारी रखेगी। जानकारी के मुताबिक इराक में अमेरिका के लगभग 2,500 सैनिक हैं। यहां अमेरिकी सैनिक आतंकवाद विरोधी अभियान और इराकी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देते हैं।
- वहीं, अब इराक के साथ नए रिश्तों पर जोर देते हुए बाइडन ने कहा कि वह बिजली की आपूर्ति को मजबूत करने, कोविड -19 से लड़ने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने और निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने में पूरी मदद करेंगे।
- बाइडन ने व्हाइट हाउस में ईराकी पीएम कादिमी को बताया कि बगदाद को दिए गए पांच लाख कोरोना रोधी वैक्सीन की खुराक कुछ हफ्ते में हो पहुंच जाएगी।

- बाइडन ने इराक में अक्टूबर में होने वाले चुनावों के लिए अमेरिकी समर्थन पर भी जोर देते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए वाशिंगटन बगदाद, खाड़ी सहयोग परिषद और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इराक के लोकतंत्र को मजबूत करने का समर्थन करते हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हैं कि चुनाव आगे बढ़े।

10. हड़प्पाई शहर धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हुआ शामिल

- 27 जुलाई, 2021 को हड़प्पा काल के शहर धौलावीरा (गुजरात) को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44 वें सत्र के दौरान धोलावीरा और रामप्पा मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अब भारत में कुल 40 साइट है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिल चुका है। बता दें कि गुजरात में अब तक तीन विश्व धरोहर स्थल है- पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी का वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद।

धौलावीरा (Dholavira)

- धौलावीरा गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। धौलावीरा को कोटडा टिंबा के नाम से भी जाना जाता है। 100 हेक्टेयर ने फैले इस स्थल की खोज वर्ष 1967-68 ईस्वी में जे. पी. जोशी ने की थी।
- यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था जो तीन भागों में विभाजित था- दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। इस स्थल की सबसे महत्त्वपूर्ण खोज यहाँ विश्व की सबसे पुरानी जल संरक्षण प्रणाली मिली है जहाँ वर्षा जल का संचयन किया जाता था।

भारत का 39वाँ विश्व धरोहर स्थल: रामप्पा मंदिर

- 25 जुलाई, 2021 को तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा मंदिर) मंदिर विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने ऐलान किया कि भारत के तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जा रहा है। सरकार ने इसका प्रस्ताव वर्ष 2019 में ही यूनेस्को को भेजा था।
- वारंगल स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है, जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया। काकतीय वंश के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में करवाया था। खास बात यह है कि इस दौर में बने ज्यादातर मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कई प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी इस मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। यह शोध का विषय भी रहा है।

- इसका निर्माण काकतिय नरेश राजा रूद्र देव ने 1163 ई. में करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के दौरान बेहतर नक्काशी और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर का प्रभावशाली प्रवेशद्वार, हजार विशाल खम्भे और छतों के शिलालेख आकर्षण केंद्र हैं। हज़ार स्तंभो वाला मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है।

विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee)

- 'विश्व धरोहर समिति'/'वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी' की बैठक साल में एक बार होती है, और इस समिति में 'अभिसमय के पक्षकार' देशों से 21 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन प्रतिनिधि सदस्यों का चुनाव 'छह साल' तक के लिए किया जाता है।
- इस समिति का मुख्य कार्य, 'विश्व विरासत अभिसमय' का कार्यान्वयन करना और 'विश्व विरासत कोष' से वित्तीय सहायता आवंटित करना है। किसी 'स्थल' को 'विश्व विरासत सूची' में शामिल किए जाने के संबंध में 'विश्व धरोहर समिति' का निर्णय अंतिम होता है।
- यह समिति, 'विश्व विरासत सूची' में शामिल स्थलों के संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट की जांच करती है और इन स्थलों को 'संकटापन्न विश्व विरासत' (World Heritage in Danger) की सूची में रखने या हटाने के विषय पर निर्णय करती है।

'विश्व धरोहर स्थलों' का संरक्षण

- 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) अर्थात 'यूनेस्को' का उद्देश्य, मानवता के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाले, पूरे विश्व में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।
- 'विश्व धरोहर स्थलों' का संरक्षण, 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय' (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) नामक एक अंतरराष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। इस संधि को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाया गया था।

'विश्व धरोहर स्थल' हेतु नामांकन प्रक्रिया

- सबसे पहले, किसी देश द्वारा अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को एक दस्तावेज में सूचीबद्ध किया जाता है, इस 'दस्तावेज' को 'संभावित सूची' (Tentative List) कहते है।
- इसके बाद, इस सूची से कुछ स्थलों का चयन करके इन्हें एक 'नामांकन फ़ाइल' (Nomination File) में रखा जाता है। फिर, 'स्मारक एवं स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद' तथा 'विश्व संरक्षण संघ' (World Conservation Union) द्वारा 'नामांकन फ़ाइल' में शामिल स्थलों का आंकलन किया जाता है।
- किसी भी देश के द्वारा, संभावित सूची में शामिल स्थलों से भिन्न स्थलों को नामित नहीं किया जा सकता है। आंकलन के पश्चात, ये संस्थाए 'विश्व धरोहर समिति' को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं।